सऊदी-ईरान तनाव को समझना

स्त्रोत – द हिन्दू

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में पश्चिम एशिया की दो प्रमुख शक्तियाँ - सऊदी अरब और ईरान, ,चीन द्वारा किए गए एक समझौते में राजनयिक संबंधों को बहाल करने पर सहमत हुए।
- 2016 में तेहरान में सऊदी दूतावास के प्रदर्शनकारियों द्वारा रियाद में एक शिया धर्मगुरु की फांसी के बाद ईरान एवं सऊदी अरब के बीच औपचारिक संबंध टूट गए थे।

समझौते के अंतर्गत शर्तें -

- सऊदी अरब और ईरान ने 2021 में एक-दूसरे से सीधे संवाद करना शुरू किया और उसके बाद बिना किसी सफलता के पहले इराक और फिर ओमान में कई दौर की वार्ता की।
- समझौते के अनुसार, ईरान, सऊदी अरब के खिलाफ और हमलों को रोकने के लिए सहमत हो गया है, विशेष रूप से यमन के हौथी-नियंत्रित हिस्सों से, (ईरान, यमन में एक शिया मिलिशिया, हौथिस का समर्थन करता है, जबकि सऊदी सरकारी बलों का समर्थन करता है) ।
- सऊदी अरब, फ़ारसी समाचार चैनल (जिसे ईरानी खुफिया ने एक आतंकवादी संगठन करार दिया है), पर नियंत्रण लगाने के लिए सहमत हो गया है।

- चीन 2023 में शांति को और मजबूत करने के लिए ईरान और छह खाड़ी देशों (सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान, जो खाड़ी सहयोग परिषद या GCC बनाते हैं) के एक क्रॉस-खाड़ी सम्मेलन की मेजबानी करने की भी योजना बना रहा है।

सऊदी अरब की ईरान तक पहुंच कैसे?

- पश्चिम एशिया हाल के वर्षों में सामरिक पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा है।
- 2020 में, UAE एक चौथाई सदी में इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने वाला पहला अरब देश बन गया।
- 2021 में, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और उनके सहयोगियों ने कतर की अपनी असफल नाकाबंदी को समाप्त करने का फैसला किया।

ईरान की समझौता स्वीकृति के कारण

- ईरान आर्थिक अलगाव और घरेलू दबाव के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है।
- ईरान, रियाल के लिए चीनी निवेश और समर्थन चाहता था। चीन ने तेहरान को 20 बिलियन डॉलर के फंड के कुछ हिस्सों को वापस लेने की अनुमति दी, जो चीनी बैंकों (अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद) के साथ जमे हुए थे। इसलिए, अलगाव और प्रतिबंधों से जूझते हुए, चीन की मध्यस्थता के तहत सऊदी अरब के साथ एक समझौता ईरान के लिए आर्थिक जीवन रेखा खोल सकता है।
- यह समझौता अरब देशों और इज़राइल को इसके खिलाफ लामबंद करने के अमेरिकी प्रयास को जटिल बना सकता है।

चीन को लाभ

- सऊदी अरब के साथ अमेरिका के संबंधों को हाल के वर्षों में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और ईरान के साथ उसके शत्रुतापूर्ण संबंध हैं, परंतु चीन के दोनों के साथ मधुर संबंध हैं - यह सऊदी तेल का एक प्रमुख खरीददार और ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- पश्चिम एशिया में शांति दूत की भूमिका निभाने में चीन के आर्थिक, क्षेत्रीय और सामरिक हित हैं।
- चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीददार है और इसके निरंतर उत्थान के लिए ऊर्जा बाजार में स्थिरता आवश्यक है। यदि सऊदी अरब और ईरान के बीच एक तनाव विशेष रूप से पश्चिम एशिया और सामान्य रूप से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में कुछ स्थिरता प्रदान कर सकता है, तो चीन को इससे लाभ होगा।

- इस क्षेत्र की सभी प्रमुख शांति पहलें हैं - कैंप डेविड समझौता (1978), ओस्लो समझौते (1993), इज़राइल-जॉर्डन संधि (1994), मध्य-पूर्व शांति संधि (2002) तथा अब्राहम समझौता (2020), इन सभी में यू.एस. की निरंतर उपस्थिति थी। लेकिन सऊदी-ईरान सुलह में, यू.एस. अनुपस्थित है।
- यह वैश्विक व्यवस्था में बड़े बदलावों की ओर इशारा करता है। इसके अलावा चीन ग्लोबल साउथ के देशों को भी स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कर रहा है।
- जबकि अमेरिका, रूस को पीछे धकेलने और प्रतिबंधों के माध्यम से मास्को को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को हथियारबंद करने के लिए पश्चिमी दुनिया को एकजुट करने में व्यस्त है।
- सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता बहुस्तरीय है - आर्थिक, भू-राजनीतिक और सांप्रदायिक।

अमेरिका का रुख

- अमेरिका, इस क्षेत्र की पारंपरिक महान शक्ति, के हाथ में अब बड़ी विदेश नीति चुनौतियां हैं जैसे कि यूक्रेन में रूसी युद्ध और भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन का उदय। अमेरिका अपनी पश्चिम एशिया नीति के दो स्तंभों - इज़राइल और अरब दुनिया - को ईरान के खिलाफ एक साथ लाना चाहता था ताकि क्षेत्र में अमेरिकी गठबंधन प्रणाली बाधित न हो।
- संयुक्त अरब अमीरात ने अब्राहम समझौते के माध्यम से इस रास्ते को चुना, सऊदी अरब ने इजरायल के साथ सामंजस्य स्थापित करने में धीमी गति से चलने का फैसला किया, खासकर जब इजरायल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हिंसा फैलती रही है।
- सऊदी तेल के बदले में अमेरिका की सुरक्षा गारंटी थी।अमेरिका अब दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादकों में से एक है और वह खाड़ी के अरबों पर उतना निर्भर नहीं है जितना कि शीत युद्ध के दौरान हुआ करता था। इसने अमेरिकी राष्ट्रपतियों को क्षेत्र में यू.एस. के विमुद्रीकरण में तेजी लाने की अनुमति दी।
- अमेरिकी अधिकारियों ने सुलह का स्वागत किया है। सार्वजनिक आख्यान यह है कि पश्चिम एशिया में दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के बीच शांति से क्षेत्र को स्थिर करने और वैश्विक ऊर्जा बाजार को लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।